

ગુજરાત ગોડલ પર નર્દે લૈંડ પુલિંગ નીતિ જાલદ

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संगाददाता

राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं लाने के लिए गुजरात मॉडल पर संशोधित लैंड पूलिंग नीति लाने जा रही है। लैंड पूलिंग स्कीम-2021 का प्रारूप तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति मिलने के बाद जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को नई लैंड पूलिंग नीति को लेकर बैठक हुई। इसमें लैंड पूलिंग स्कीम-2021 के प्रारूप को रखा गया। इस पर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया, जिससे किसी तरह नई रेंज-रीट-रेट ताकि उन्हें नए

मुख्यमंत्री के निर्देश पर¹ तैयार हुई है यह नीति

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आवास विभाग ने संशोधित लैंड पूलिंग नीति तैयार की है। आवास विभाग फरवरी 2019 में पहली बार लैंड पूलिंग नीति लेकर आया था। इसमें कई तरह की खामियां होने की वजह से शहरी क्षेत्रों में जरूरत के आधार पर जमीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसीलिए यूपी के अधिकारियों को गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली राज्यों की नीति को देखने के लिए भेजा गया। गुजरात मॉडल सबसे बेहतर पाया गया है।